खंड . 2 अंक . 8 मार्च 2020

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

संदेश

आर.के. जैन
अध्यक्ष, के.ज.आ

भारत सरकार, सिंधु जल संधि के तहत पूर्वी नदियों के पानी के पूर्ण उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है. तदनुसार, जम्मू-कश्मीर में उझ बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, राज्य मंत्री पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष तथा श्री रतन लाल कटारिया, केंद्रीय राज्य मंत्री, जल शक्ति और सामाजिक न्याय व अधिकारिता द्वारा 03.02.2020 को संयुक्त रूप से एक बैठक आयोजित की गई.

के.ज.आ. देश में नदियों और जलाशयों में तलछट प्रबंधन के लिए नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, माननीय जल शक्ति मंत्री ने ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. एवं के.ज.आ. के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 10.02.2020 को एक बैठक की जिसमें तलछट प्रबंधन नीति के मसौदे की समीक्षा की गई और बैठक के दौरान विभिन्न सुझाव दिए. तदनुसार, नीति के मसौदे को संशोधित किया जा रहा है.

ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. द्वारा "बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन" के लिए गठित समिति की पहली बैठक 20.02.2020 को के.ज.आ. नई दिल्ली में मेरी अध्यक्षता में आयोजित की गई. समिति ने एनएचपी के अंतर्गत सलाहकार द्वारा किए जाने वाले अध्ययन हेतु विचारार्थ विषय को अंतिम रूप दिया.

तिलैया धाधर विपथन योजना के अंतर्गत तिलैया जलाशय से लेकर गंगा बेसिन के हरोहर उप-बेसिन तक पानी के विपथन के मुद्दे पर बिहार और झारखंड राज्यों के बीच विवाद को हल करने के लिए, मंत्रालय द्वारा अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक वार्ता समिति का गठन किया गया है. समिति की पहली बैठक 13.02.2020 को आयोजित की गई, जिसके दौरान विवाद के विभिन्न पहलुओं और समाधान के लिए संभावित आधारों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया.

मंत्रालय द्वारा इसी तरह की वार्ता समिति तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच पेन्नैयर नदी जल विवाद के लिए भी गठित की गई है. इस समिति की पहली बैठक 24.02.2020 को आयोजित की गई. दोनों समितियों का गठन अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अनुसार किया गया है.

ब्रिक्स देशों के जल मंत्रियों की बैठक निकट भविष्य में भारत में आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है. मेरे साथ इस संबंध में प्रारंभिक चर्चा के बाद, इस बैठक के विषय और कार्यसूची तय करने हेतु श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में 24.02.2020 को नई दिल्ली में एक विस्तृत बैठक हुई. इस बैठक का संभावित मुख्य विषय "ज्ञान साझाकरण, समावेशी विकास और सतत जल संसाधन प्रबंधन - 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना " तय किया गया है.

दिनांक 26 से 28 फरवरी 2020 के दौरान आईआईटी, रुड़की और एनआईएच, रुड़की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रथम रुड़की वाटर कॉन्क्लेव 2020 में केंद्रीय जल आयोग के कई अधिकारियों द्वारा जल क्षेत्र में उनके सक्रियता से भाग लेने और अनुभव को साझा करते हुए देखकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई. यह आयोजन द्विवार्षिक रूप से आयोजित करने की योजना है.

फरवरी 2020 के अंत में के.ज.आ की डिजाइन टीम ने कर्नाटक के कृष्णराजसागर बांध का दौरा किया, जो 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है. यह दौरा विभिन्न बांध फाटकों और उनके उत्थापन व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए किया गया था जिन्हें डीआरआईपी के प्रावधानों के तहत के.ज.आ द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजाइन परामर्शी के अनुसार बदला जाना है.

राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे में आयोजित अपने 24-सप्ताह के लंबे प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद, के.ज.आ.-मुख्यालय, नई दिल्ली में के.ज.अ.से. समूह- 'क' के 44 अधिकारियों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई. मैंने दिनांक 10.02.2020 को के.ज.आ.-मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित उनके प्रशिक्षण समापन समारोह में इन युवा अधिकारियों के साथ बातचीत की. मैं उन सभी के सफल और सुखद भविष्य की कामना करता हूं.

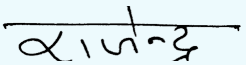

केंद्रीय जल आयोग (तत्कालीन केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नेविगेशन आयोग) की स्थापना 05.04.1945 को हुई.

डॉ बी.आर. अम्बेडकर ने केंद्र में इस तरह के तकनीकी निकाय होने की आवश्यकता के लिए न केवल इस विचार को जागृत किया और अपना तर्क रखा, बल्कि इसके उद्देश्यों, संगठनात्मक संरचना और कार्यक्रम को भी निर्धारित किया.

सीडब्लूएनआईसी की स्थापना हेतु अंतिम प्रस्ताव को जलमार्ग, सिंचाई और नेविगेशन के लिए भारत सरकार के परामर्शदाता अभियन्ता, राय बहादुर ए.एन. खोसला की सहायता से तत्कालीन श्रम विभाग ने तैयार किया.

डॉ. ए.एन. खोसला को बाद में सीडब्लूएनआईसी का संस्थापक अध्यक्ष नियुक्त किया गया.

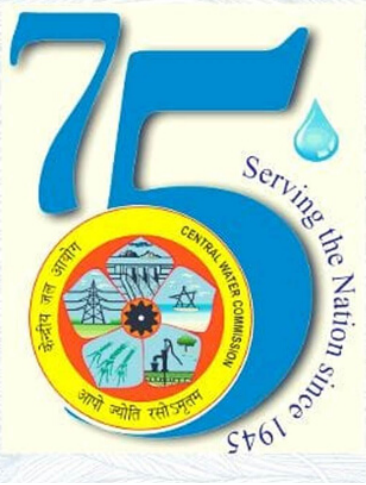

केंद्रीय जल आयोग के 75 वर्ष

डॉ बी.आर. अम्बेडकर
सदस्य (श्रम)
वायसराय की कार्यकारी परिषद
(1942-1946)

"मेरी कल्पना है कि समय बीतने के साथ साथ यह निकाय एक बहुत बड़े संगठन के रूप में विकसित होगा जिसकी गतिविधियां सम्पूर्ण भारतवर्ष में फैलेंगी. इसकी सहायता और सलाह के लिए प्रत्येक प्रान्त और राज्य आतुर रहेगा ताकि किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिकतम लाभ और एकीकृत विकास के लिए किया जा सके."

विषय-वस्तु

- तलछट प्रबंधन के लिए माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की बैठक
- उझ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए बैठक
- अटल भूजल योजना पर कार्यशाला
- जल विवाद के लिए वार्ता समितियों की बैठकें
- रुड़की वाटर कॉन्क्लेव -2020
- फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर बैठक
- ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक के लिए तैयारी
- पश्चिम बंगाल की प्रमुख सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन परियोजना
- आईएसआरडब्लूडी नियमों के लिए मसौदा समिति की बैठक
- भारत बांग्लादेश संयुक्त समिति की बैठक
- बीआईएस की सेक्शनल कमेटी - डब्लूआरडी 09 की बैठक
- भूटान में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा
- डीआरआईपी
- हर काम देश के नाम
- जलाशय प्रबोधन
- आइज़ोल में भूस्खलन
- फरक्का बैराज के लिए टीएसी की बैठक
- के.ज.अ.से. समूह 'क' अधिकारियों के लिए 31वें आईटीपी का समापन
- सीबीआईपी पुरस्कार
- इतिहास- एनडब्लूए

भारतीय नदियों के लिए एक संशोधित तलछट प्रबंधन नीति हेतु माननीय केंद्रीय मंत्री जल शक्ति द्वारा बैठक

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, माननीय जल शक्ति मंत्री ने ज.सं.न.वि एवं गं.सं.वि और के.ज.आ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 10.02.2020 को एक बैठक में तलछट प्रबंधन नीति के मसौदे की समीक्षा की और इस बैठक के दौरान विभिन्न सुझाव दिए.

उझ बहुउद्देशीय परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए बैठक

डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, राज्य मंत्री पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष तथा श्री रतन लाल कटारिया, केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति और सामाजिक न्याय व अधिकारिता ने जम्मू-कश्मीर में उझ बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए 03.02.2020 को संयुक्त रूप से एक बैठक आयोजित की. इस बैठक में सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. के साथ-साथ जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा पंजाब राज्य और जम्मू-कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के अधिकारियों ने भाग लिया.

सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों का तेजी से उपयोग करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार, इस परियोजना का निर्माण जम्मू व कश्मीर के कठुआ जिले में उझ नदी पर करने की योजना है जो रावी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है. यह परियोजना उझ नदी के लगभग 781 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को संग्रहित करेगी. इस परियोजना के निर्माण के बाद सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को आवंटित पूर्वी नदियों के पानी का उपयोग उस अप्रयुक्त प्रवाह का उपयोग करके बढ़ाया जाएगा जो वर्तमान में सीमा पार बह जाता है. इसके लिए लगभग रु. 5850 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना की डीपीआर को पहले ही जनवरी, 2019 में जल शक्ति मंत्रालय, ज.सं.न.वि एवं गं.सं.वि. की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें 248 एमसीएम के खपतकारी उपयोग की परिकल्पना की गई है, जिसके बाद भी बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त जल छूट रहा है. जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त कमान क्षेत्र की पहचान करके उझ के पानी के उपयोग को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

अटल भूजल योजना पर कार्यशाला

जल शक्ति मंत्रालय, ज.सं.न.वि एवं गं.सं.वि. द्वारा दिनांक 12.02.2020 को योजना के कार्यान्वयन को अग्रसर करने के लिए अटल भूजल योजना (अटल जल) पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला की अध्यक्षता श्री रतन लाल कटारिया, केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता ने की. इस कार्यशाला में मंत्रालय, भाग लेने वाले राज्यों के अधिकारियों, विश्व बैंक के अधिकारियों और प्रमुख गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया. इसमें श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग भी उपस्थित रहे. इस कार्यशाला में सहभागी भूजल प्रबंधन पर चर्चा हुई और योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रारंभिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया.

जल विवादों के समाधान के लिए वार्ता समितियों की बैठकें

दिनांक 13.02.2020 को वार्ता समिति की बैठक

बिहार सरकार ने दिनांक 04.01.2018 को अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत अधिकरण को तिलैया धाधर विपथन योजना से संबंधित मामले को संदर्भित करने के लिए केंद्र को एक आवेदन किया. बिहार सरकार के अनुसार, तिलैया धाधर विपथन योजना की कल्पना अविभाजित बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच 1978 के अंतर-राज्यीय समझौते के प्रावधानों के तहत की गई थी, जिसे कुछ शर्तों के अधीन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) में भी 31.05.2000 को मंजूरी दी गई थी. हालाँकि, झारखंड सरकार, झारखंड राज्य के भीतर पानी की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण तिलैया जलाशय से गंगा बेसिन के हरोहर उप-बेसिन में पानी के विपथन के लिए सहमत नहीं हो रही है. ज.सं.न.वि एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय ने आईएसआरडब्लूडी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (1) के अनुसार तिलैया-धाधर विपथन योजना के विवाद के समाधान के लिए 06.01.2020 को अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में वार्ता समिति का गठन किया. वार्ता समिति की पहली बैठक 13.02.2020 को के.ज.आ.-मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई.

इसी तरह, पेन्नैयर और उसकी सहायक नदियों के पानी से संबंधित विवाद पर वार्ता समिति की पहली बैठक 24.02.2020 को अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में आयोजित की गई. यह विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच है. बेसिन के अन्य राज्य जैसे आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया.

रुड़की वाटर कॉन्क्लेव -2020

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा संयुक्त रूप से 26 से 28 फरवरी 2020 के दौरान प्रथम रुड़की वाटर कॉन्क्लेव (आरडब्लूसी) - 2020, द्विवार्षिक रूप से परिकल्पित आयोजन किए जाने वाले एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित किया गया. आरडब्लूसी-2020 का विषय "जलवायु परिवर्तन के जल विज्ञान संबंधी पहलु" था, जिसमें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक चुनौतियों, ऊर्जा, सादे जल और भोजन आदि की मांग से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया.

श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. आरडब्ल्यूसी- 020 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे. सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने जल संसाधनों पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दूर करने हेतु नए तंत्र तैयार करने पर जोर दिया. उन्होंने देश में जल संसाधन प्रबंधन के बारे में कॉन्क्लेव के दौरान मुख्य भाषण भी दिया.

कॉन्क्लेव में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों / संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, सरकारी संगठनों, नियोजकों और निर्णय निर्माताओं, फील्ड कर्मियों, परामर्शदाता, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने भाग लिया.

श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय कॉन्क्लेव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे. केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने कॉन्क्लेव में सक्रिय रूप से भाग लिया और तालिका में दिए गए विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से जल क्षेत्र में अपने अनुभवों को साझा किया.

1.	केरल के जलाशयों के लिए संभाव्यता आधारित नियम स्तर	श्री ऋषि श्रीवास्तव, निदेशक
2.	सतही जल और भूजल की अंत:क्रिया और भारत के संदर्भ में इसका खपतकारी (कन्जंक्टिव) उपयोग	श्री गोवर्धन प्रसाद, निदेशक
3.	उन्नत जल वैज्ञानिक और जल - मौसम संबंधी उपकरण	श्री राजेश कुमार, निदेशक
4.	बाढ़ क्षेत्र वर्गीकरण	श्री मो. फैज सैयद, उप निदेशक
5.	जल उपयोग क्षमता में वृद्धि	श्री अर्जेश मधोक, उप निदेशक
6.	जलाशय की सक्रिय भंडारण क्षमता में नुकसान के आकलन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी	श्रीमती करिश्मा भटनागर मल्होत्रा, उप निदेशक
7.	भूकंपीय संकट आकलन सूचना उपकरण	श्री सत्यम अग्रवाल, उप निदेशक
8.	पुनात्सांगछु - II जलविद्युत परियोजना (1020 मेगावाट), भूटान के अनुप्रवाह सर्ज गैलरी के पुनरुद्धार हेतु जलीय क्षणिक अध्ययन (हाइड्रोलिक ट्रांसिएंट स्टडीज)	श्री अमित गुप्ता, सहायक निदेशक

बिहार में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर समिति की पहली बैठक

ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए अध्यक्ष, के.ज.आ. के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई, जिसमें आयुक्त(एफएम) ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि.; मुख्य अभियंता(एचएसओ), के.ज.आ.; निदेशक, एनआईएच; बिहार सरकार के प्रतिनिधि और निदेशक (वित्त) सदस्य के रूप में शामिल हैं.

इस समिति की पहली बैठक दिनांक 20.02.2020 को के.ज.आ. मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित हुई. एक सलाहकार के माध्यम से किए जाने वाले प्रस्तावित अध्ययन के लिए मसौदा विचारार्थ विषय (टीओआर) पर विस्तृत चर्चा की गई. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने अध्ययन के लिए विचारार्थ विषय को अंतिम रूप दिया. यह अध्ययन 12 महीने की समयावधि के भीतर पूर्ण होने की संभावना है.

भारत में ब्रिक्स देशों के जल मंत्रियों की बैठक

भारत में ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक के आयोजन हेतु विषय और कार्यसूची तैयार करने के लिए श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक 24.02.2020 को नई दिल्ली में आयोजित की गई. इस बैठक में श्री पी. हरीश, एएस(एमईआर), विदेश मंत्रालय, श्री भोपाल सिंह, डीजी, एनडब्लूडीए और डीओडीडब्ल्यूएंडएस, सीजीडब्ल्यूबी, एनडब्ल्यूडीए तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया. इस बैठक में ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक का विषय इस प्रकार तय किया गया :

क. मुख्य विषय
"ज्ञान साझाकरण, समावेशी विकास और सतत जल संसाधन प्रबंधन - 21वीं सदी की चुनौतियां"

ख. उप-विषय
i) जल प्रबंधन में तकनीकी नवाचार,
ii) नदी संरक्षण और ई - प्रवाह,
iii) जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना - चुनौतियां और अवसर,
iv) जल, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा का समाधान करना.

इस बैठक में अक्टूबर 2020 के दौरान डीओडीडब्ल्यूएंडएस द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम - जल जीवन मिशन कार्यक्रम के साथ-साथ ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया गया. ब्रिक्स कार्यक्रम को डीओडीडब्ल्यूएंडएस कार्यक्रम के साइड इवेंट के रूप में रखने के लिए आगे के तौर-तरीके तय करने हेतु, विदेश मंत्रालय का एमईआर प्रभाग एक अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित करेगा.

के.ज.आ. के अधिकारियों का अर्जुन सहायक परियोजना (कबरई बांध) का दौरा

के.ज.आ. की डिजाइन टीम में शामिल श्री ए.के. जैन, निदेशक, श्री रणधीर चौधरी, उप-निदेशक और श्री अन्निपु प्रवीण, उप-निदेशक ने 28.02.2020 को अर्जुन सहायक परियोजना (कबरई बांध), जिला महोबा, उत्तर प्रदेश का दौरा किया.
इस स्थल का दौरा कंक्रीट उत्प्लाव (स्पिलवे) के साथ मृदा बांध की चल रही निर्माण गतिविधि के निरीक्षण और बांध निकाय के भीतर मुख्य नियामक / स्लूइस आउटलेट हेतु उपयुक्त स्थान की पहचान करने के लिए किया गया था.

भूकंपीय संकट मूल्यांकन सूचना प्रणाली पर चर्चा के लिए बैठक

आईआईटी, रुड़की और सीडब्लूपीआरएस, पुणे द्वारा विकसित भूकंपीय संकट मूल्यांकन सूचना प्रणाली (एसएचएआईएसवाईएस) की प्रगति पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक बैठक 04.02.2020 को के.ज.आ. मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई.

पश्चिम बंगाल की प्रमुख सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना पर समीक्षा बैठक

विश्व बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की बाह्य सहायता के लिए प्रस्तावित पश्चिम बंगाल बृहद सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन परियोजना पर एक समीक्षा बैठक श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में 26.02.2020 को आयोजित की गई. विश्व बैंक से श्री एल्जस्ब्रैंड हर्कोड जोंग, लीडर जल संसाधन और के.ज.आ. से श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता(आईएमओ), श्री जी.के. अग्रवाल, मुख्य अभियंता(पीएओ), श्री अनंत गुप्ता, निदेशक(ईए) तथा श्री किरण प्रमानिक, निदेशक(पीए), पूर्वोक्त बैठक में शामिल हुए.

देश में बाह्य सहायता विभिन्न रूपों में जैसे कि बहुपक्षीय या द्विपक्षीय सहायता, अन्य देशों से ऋण, अनुदान और वस्तु सहायता तथा अन्य दाता एजेंसियों जैसे कि विश्व बैंक, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से प्राप्त होती है. जल शक्ति मंत्रालय और उसके संगठन, देश में जल संसाधनों के तेजी से विकास के लिए धन और नवीनतम तकनीकी दोनों के संदर्भ में, संसाधनों की कमी को पूर्ण करने के लिए विभिन्न वित्तपोषक एजेंसियों से बाहरी सहायता प्राप्त करने में राज्य सरकारों की सहायता करते हैं.

आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), भारत सरकार इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है. के.ज.आ., ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय की तकनीकी शाखा होने के नाते, बाह्य सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जल क्षेत्र के प्रस्तावों की जांच करती है.

आईएसआरडब्लूडी नियमों पर मसौदा समिति की चौथी बैठक

मौजूदा अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद नियम, 1959 में संशोधन करके मसौदा नियमों को तैयार करने के लिए गठित समिति की चौथी बैठक सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 07.02.2020 को के.ज.आ., मुख्यालय, नई दिल्ली में हुई. संशोधित मसौदा नियमों पर विस्तार से चर्चा की गई और इससे संबंधित कुछ बिंदुओं को जोड़ने का निर्णय लिया गया
(i) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, मूल्यांकनकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति के लिए पैनल
(ii) अभिलेखों के हस्तांतरण का प्रोटोकॉल, तथा
(iii) मौजूदा वार्ता समितियों का अधिकरण के डीआरसी के तौर पर कार्य करने हेतु

अधिकरण के लिए कुछ संगठनात्मक ढांचे का सुझाव देना भी तय किया गया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में बताया गया. समिति के सदस्यों के सुझावों / विचारों को शामिल करने के बाद अंतिम मसौदा नियम जल्द ही ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है.

गंगा के जल बंटवारे पर भारत बांग्लादेश संयुक्त समिति की बैठक

बांग्लादेश के प्रतिनिधि मंडल ने कोलकाता में गंगा के पानी के बंटवारे पर भारत-बांग्लादेश की संयुक्त समिति की 73वीं और 74वीं बैठक के साथ-साथ फरक्का, भारत में संयुक्त निस्सरण (डिस्चार्ज) माप स्थल पर दौरा करने के लिए 24 से 28 फरवरी 2020 के दौरान भारत का दौरा किया. भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री अतुल जैन, आयुक्त(एफएम), ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. ने किया. के.ज.आ. से श्री रजत शर्मा, उप निदेशक, जल विज्ञान(एनई) निदेशालय ने कोलकाता में दोनों पक्षों की बैठक में भाग लिया और फरक्का में निस्सरण का संयुक्त प्रेक्षण किया.

बीआईएस के बांध और उत्प्लाव (स्पिलवेज) सेक्शनल कमेटी डब्ल्यूआरडी 09 की 18 वीं बैठक

बीआईएस की बांधों और स्पिलवेज सेक्शनल कमेटी डब्ल्यूआरडी 09 की 18वीं बैठक श्री टी.के. शिवराजन, मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 12.02.0220 को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), मानक भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई. इस बैठक में राज्य के इंजीनियरिंग विभागों, अनुसंधान संस्थानों, आईआईटी, पीएसयू, निजी फर्मों और केंद्रीय जल आयोग जैसे विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया.

बांध में कोल्ग्रोउट चिनाई-अभ्यास संहिता, स्पिलवे के साथ मृदा बांध का जंक्शन, एनओएफ और निर्गमों (आउटलेटस) – दिशा निर्देश के मसौदा दस्तावेजों पर कई कार्यसूची बिंदुओं पर चर्चा हुई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया.

इस समिति ने स्पिलवे और आउटलेट संरचनाओं के लिए वातन (एरेशन) मांग के आकलन हेतु मापदंड (आईएस 12804 का पहला संशोधन), हाई ओगी ओवरफ़्लो स्पिलवे के हाइड्रोलिक डिजाइन हेतु सिफारिशों (आईएस 6934 का दूसरा संशोधन) जैसे तैयार किए जा रहे मसौदा दस्तावेजों के विभिन्न पहलुओं और नए विषयों जैसे सुरंग और शाफ्ट स्पिलवेज, डैम ब्रेक विश्लेषण, स्टेप्ड स्पिलवेज के हाइड्रोलिक डिजाइन, रोलर कॉम्पेक्टेकड कंक्रीट (आरसीसी) बांध के डिजाइन और निर्माण, कंक्रीट मृदा-शैल (रॉक फिल) बांध (सीएफआरडी) के अन्वेषण के लिए भी चर्चा की. इस समिति ने अपने सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जिन्हें भविष्य में मानकों की तैयारी हेतु विचारार्थ रखा जा सकता है.

भूटान में जलविद्युत परियोजनाओं की समीक्षा के लिए अंतर-मंत्रालयी बैठक

भूटान में पुनात्सांगछू - I जल विद्युत परियोजना (1200 मेगावाट), पुनात्सांगछू - II जल विद्युत परियोजना (1020 मेगावाट), मंगदेछु जल विद्युत परियोजना (720 मेगावाट) के निर्माण की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 13.02.2020 को भारत सरकार के विदेश सचिव द्वारा एक अंतर-मंत्रालयी बैठक की गई. इस बैठक में डॉ. आर.के. गुप्ता, सदस्य(डीएंडआर), और श्री विवेक त्रिपाठी, निदेशक, के.ज.आ. ने भाग लिया.

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी)

डॉ. आर.के. गुप्ता, सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में डीआरआईपी - II हेतु कार्यशाला का आयोजन विभिन्न साझेदार एजेंसियों द्वारा तैयारी की गतिविधियों की स्थिति और उसी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 25.02.2020 को नई दिल्ली के शांगरी-ला इरोस होटल में किया गया. इस कार्यशाला में विश्व बैंक, डीआरआईपी चरण II और चरण III की कार्यान्वयन एजेंसियों तथा के.ज.आ. के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.

डीआरआईपी -II हेतु कार्यशाला

मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में 18.02.2020 को आपातकालीन कार्य योजना(ईएपी) पर हितधारकों की एक दिवसीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खराड़ी बांध, मूरुमनाला बांध, नाहलरसारा बांध और सारथी बांध से संबंधित ईएपी प्रस्तुत किए गए. इस कार्यशाला में के.ज.आ., एनडीएमए, एसडीएमए, आईएमडी, एनआरएससी, जीएसआई, बांध प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों तथा जिले के प्राधिकारियों, बांध के अनुप्रवाह क्षेत्र के ग्रामीणों ने भाग लिया.

ईएपी के लिए हितधारकों की परामर्श बैठक

हर काम देश के नाम

भारत सरकार ने फरवरी 2020 के दौरान "हर काम देश के नाम" से एक अभियान शुरू किया जिसमें सभी मंत्रालयों को जनता तक पहुँच के लिए सामग्री तैयार करनी थी. के.ज.आ., मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी इस गतिविधि में भाग लिया और छोटे वीडियो व प्रचार सामग्री तैयार की गई थी तथा सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्रसार प्लेटफार्मों के माध्यम से साझा किया गया.

जलाशय प्रबोधन

केन्द्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश भर के 123 जलाशयों की वर्तमान भंडारण स्थिति की देखरेख करता है और हर ब्रहस्पतिवार को इसका एक बुलेटिन जारी करता है. इन 123 जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 171.091 बीसीएम है जो देश में निर्मित अनुमानित 257.812 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 66.36 % है.

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 27.02.2020 के अनुसार इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण 101.873 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल सक्रिय धारण क्षमता का 60% है. हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान उपलब्ध सक्रिय भंडारण 65.15 बीसीएम और पिछले 10 वर्ष में सक्रिय औसत भंडारण 68.37 बीसीएम था. इस प्रकार इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान सक्रिय भंडारण का 156% है और पिछले 10 वर्ष की औसत भंडारण का 149% है.

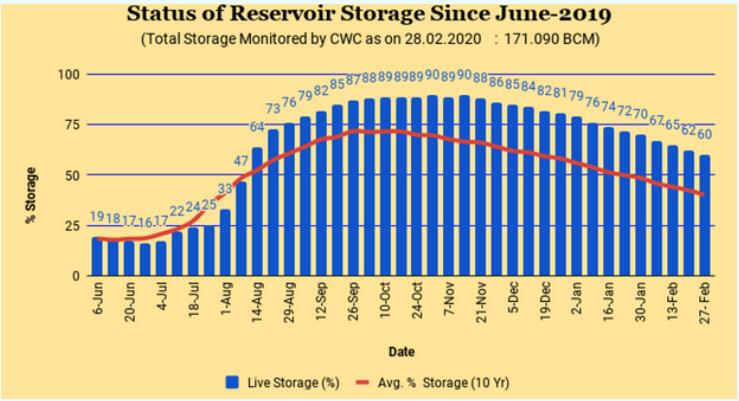

आइज़ोल में भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को के.ज.आ. द्वारा अस्थायी आश्रय का प्रावधान

के.ज.आ. परिसर, जलशक्तिपुरम, ज़ेमाबॉक, आइज़ोल से महज 200 मीटर की दूरी पर ज़ेमाबॉक में भूमि की खुदाई के कारण भूमि में दरारें उत्पन्न हो गई. उत्पन्न दरारों के कारण, क्षेत्र कमजोर हो गया और भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होने के नाते जिला आयुक्त ने मानवीय आधार पर के.ज.आ. परिसर में 10 परिवारों को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए अधिशासी अभियंता, एनईआईडी-II, के.ज.आ. आइज़ोल से 27.01.2020 को संपर्क किया. के.ज.आ, आइज़ोल कार्यालय ने उस भूमि दरार जिसके परिणामस्वरूप अंततः ज़ेमाबॉक में 02.02.2020 को भूस्खलन और नुकसान हुआ,से प्रभावित 10 (दस) परिवारों को अस्थायी आश्रय प्रदान किया. प्रभावित परिवारों को समय पर आश्रय प्रदान करके, के.ज.आ. ने लोगों के जीवन को बचाने में मुख्य भूमिका निभाई.

दौरे

1. अध्यक्ष, के.ज.आ. का एचजीडी, देहरादून के अंतर्गत स्थलों का दौरा

के.ज.आ. देश भर में 1600 से अधिक हाइड्रो-मेट प्रेक्षण स्थलों के एक नेटवर्क की देखरेख कर रहा है. इन स्थलों पर एकत्रित आंकड़ों की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है और इसे सुनिश्चित करने के लिए उचित निगरानी प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है. इस संदर्भ में श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. ने 27.02.2020 को हिमालयी गंगा डिवीजन, के.ज.आ., देहरादून के अंतर्गत विभिन्न स्थलों नामतः दोसनी, रायसी और शुक्रताल का दौरा किया.

अध्यक्ष, के.ज.आ. का एचजीडी, देहरादून के अंतर्गत स्थलों का दौरा

2. सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. का पूर्वी कोसी नहर परियोजना दौरा

श्री एस.के हलधर, सदस्य(डब्लूपीएंडपी) के नेतृत्व में श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ) और श्री अमित मित्तल, उप निदेशक के साथ के.ज.आ. के अधिकारियों के एक दल ने 18 से 20 फरवरी 2020 के दौरान परियोजना के परियोजनोपरांत पर्यावरण (सामाजिक भी) अध्ययन की जमीनी वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए पूर्वी कोसी नहर परियोजना का दौरा किया. इस दौरे के दौरान, के.ज.आ. की टीम ने जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की.

परियोजनोपरांत पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य जल संसाधन परियोजनाओं के अनुकूल और प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक दोनों प्रभावों का आकलन करना है और प्रतिकूल प्रभावों को जहाँ तक हो सके कम करने के लिए पर्यावरणीय योजनाओं को तैयार करना है.

सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. का पूर्वी कोसी नहर परियोजना का दौरा

3. सदस्य(आरएम) का ब्रह्मपुत्र बेसिन दौरा

श्री आर.के. सिन्हा, सदस्य(आरएम), के.ज.आ. ने 19 से 22 फरवरी 2020 के दौरान यूबीडी, डिब्रूगढ़ और एनईआईडी-III, ईटानगर के संबंधित कार्यकारी अभियंताओं के साथ अरुणाचल प्रदेश और ऊपरी असम में विभिन्न जल वैज्ञानिक प्रेक्षण और हिम प्रमापी (स्नो गेज) स्थलों का निरीक्षण किया.

यह निरीक्षण अरुणाचल प्रदेश में सियुम नदी के तीन स्थलों, सियांग नदी के दो स्थलों और दिबांग नदी के एक स्थल तथा असम में लोहित नदी के एक स्थल पर किया गया. उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में हिम प्रमापी और मौसम विज्ञान स्थल का भी दौरा किया.

सदस्य(आरएम), के.ज.आ. का अरुणाचल प्रदेश में मेचुका का दौरा

4. कृष्णराजसागर बांध, कर्नाटक का निरीक्षण दौरा

के.ज.आ. के डीएंडआर विंग से श्री एम. लाल, मुख्य अभियंता, श्री हरकेश कुमार, निदेशक, श्री कयूम मोहम्मद, निदेशक और श्री आदित्य मिश्रा, उप-निदेशक की टीम ने 27.02.2020 से 01.03.2020 तक कर्नाटक के कृष्णराजसागर (केआरएस) बांध का दौरा किया.

इस टीम ने 136 गेटों और 2 क्रेनों के 136 नए गेट्स द्वारा प्रस्तावित प्रतिस्थापन तथा विभिन्न स्थानों पर 136 स्किड माउंटेड कॉम्पैक्ट हॉइस्ट को लगाने के प्रावधान और हाइड्रो-मैकेनिकल उपकरणों की स्थापना से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में उनके उत्थापन तंत्र और उसके एंबेडेड पार्ट्स की उपयुक्तता की जांच करने के लिए बांध स्थल का दौरा किया. स्थल के दौरे के दौरान कर्नाटक जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी साथ थे.

कावेरी नदी पर कर्नाटक के मांड्या जिले के श्रीरंगापटना तालुक में स्थित, केआरएस बांध सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाएँ और दाएँ किनारे पर नहर प्रणालियों में तथा बांध के नीचे विकसित बृंदावन गार्डन में मनोरंजक सुविधाओं के लिए पानी का प्रवाह करता है. यह बांध हेमवती और लक्ष्मणतीर्थ नदियों के साथ कावेरी नदी के संगम

के नीचे स्थित है. इस बांध की कुल लंबाई 2.6 किलोमीटर है और यह पत्थर की चिनाई के साथ जोड़ने वाले सुरखी मोर्टार से बनाया गया है. इस बांध का निर्माण 1932 में पूरा हुआ और तब से इसका संचालन हो रहा है.

पोलावरम सिंचाई परियोजना पर बैठक

पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश में डिजाइन के कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए के.ज.आ की डिजाइन(एनडब्लूएंडएस) यूनिट के अधिकारियों और प्रो. जी.वी. रमना आईआईटी दिल्ली के बीच दिनांक 26.02.2020 को के.ज.आ., नई दिल्ली में एक बैठक हुई. पोलावरम में इस्तेमाल की जा रही जमीन सुधार तकनीकों के बारे में बहुत उपयोगी चर्चा हुई और इस बात पर सहमति हुई कि चुनौतीपूर्ण नींव के लिए पत्थर के स्तंभों और डीप सॉइल मिक्सिंग तकनीकों का उपयोग करना होगा.

फरक्का बैराज की टीएसी की 115 वीं बैठक

डॉ. आर.के. गुप्ता, सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में फरक्का बैराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की 115वीं बैठक 20 से 21 फरवरी 2020 के दौरान फरक्का में आयोजित की गई. इस बैठक में विभिन्न डिजाइन मुद्दों और उनके समाधान पर चर्चा करने के लिए विभिन्न संगठनों जैसे के.ज.आ., आईडब्ल्यूएआई, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, डब्ल्यूआरडी-बिहार, डब्ल्यूआरडी-बंगाल, एनटीपीसी-फरक्का आदि के अधिकारियों ने भाग लिया.

के.ज.अ.से. समूह 'क' अधिकारियों के 31वें प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन

केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा (सीडब्ल्यूईएस) समूह 'क' अधिकारियों के लिए 31वें प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) का समापन सत्र दिनांक 10.02.2020 को के.ज.आ. , मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया. अध्यक्ष, के.ज.आ. और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा में वृद्धि हुई. कुल 44 नए शामिल अधिकारियों ने 24 सप्ताह लंबी आईटीपी में भाग लिया, जो 19.08.2019 को शुरू हुआ था और इसमें दो सप्ताह के भारत दर्शन का घटक भी समिल्लित था. इस अवसर पर प्रशिक्षु अधिकारियों को पुरस्कार और प्रशिक्षण समापन प्रमाण पत्र वितरित किए गए.

श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए

श्री तरुण सिंह, स.नि. (प्रथम पुरस्कार)

श्री अबुज़र गफारी, स.नि. (दूसरा पुरस्कार)

श्री बंदला हेमादित्य, स.नि.
(संयुक्त तृतीय पुरस्कार)

श्री मधुकांत गोयल, स.नि.
(संयुक्त तृतीय पुरस्कार)

सुश्री लोवी अग्रवाल, स.नि.
(संयुक्त सांत्वना पुरस्कार)

श्री धर्मेंद्र चौहान, स.नि.
(संयुक्त सांत्वना पुरस्कार)

अन्य प्रशिक्षण गतिविधियाँ

(i)कृष्णा एवं समन्वय परिमंडल, के.ज.आ., हैदराबाद ने 11 से 14 फरवरी 2020 के दौरान प्रशिक्षण भवन, केजीबीओ, हैदराबाद में जल वैज्ञानिक प्रेक्षणों, जल गुणवता, दुरमापी (टेलीमेट्री) प्रणाली और ई-एसडब्ल्यूआईएस पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया. प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन श्री एम.के. श्रीनिवास, मुख्य अभियंता द्वारा किया गया. उद्घाटन समारोह में श्री पी. देवेंद्र राव, अधीक्षण अभियंता भी शामिल हुए. उपरोक्त प्रशिक्षण कृष्णा और गोदावरी बेसिन संगठन के अधिकारियों द्वारा 25 कर्मचारियों को प्रदान किया गया, जिनमें कुशल कार्य सहायक, एमटीएस और आउटसोर्स पर्यवेक्षक / अनुसंधान सहायक शामिल हैं जो जल वैज्ञानिक प्रेक्षण का कार्य करतें हैं.

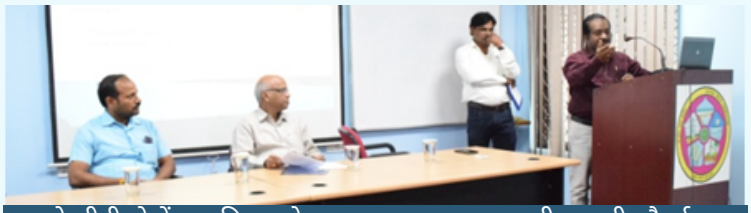
केजीबीओ में जल विज्ञान प्रेक्षण, जल गुणवत्ता, दूरमापी प्रणाली और ई-एसडब्लूआईएस पर प्रशिक्षण

"एकीकृत पाइप सिंचाई नेटवर्क और सूक्ष्म सिंचाई" के डिजाइन पहलुओं पर व्याख्यान

(ii)मुख्य अभियंता, डिजाइन(ईएंडएनई), के.ज.आ. ने 14.02.2020 को जयपुर (राजस्थान) में "एकीकृत पाइप सिंचाई नेटवर्क और सूक्ष्म सिंचाई" के डिजाइन पहलुओं पर एक व्याख्यान दिया. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के लिए केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड (सीबीआईपी) द्वारा आयोजित किया गया.

एफएलएसी 2डी और 3डी अभिकल्प सॉफ़्टवेयर पर प्रशिक्षण

(iii)के.ज.आ. द्वारा सेवा भवन में 03 से 05 फरवरी 2020 और 10 से 12 फरवरी2020 के दौरान एफएलएसी 2डी और 3डी डिजाइन सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया. इसमें डीएंडआर विंग, के.ज.आ. के अधिकारियों ने भाग लिया. यह प्रशिक्षण दो आयामी और तीन आयामी मॉडल में मिट्टी, चट्टान, भूजल और भू-आधार के उन्नत भू-तकनीकी विश्लेषण के उद्देश्य से किया गया.

जल क्षेत्र - समाचार

- जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ मिले (हिंदुस्तान, 02.02.2020)
- नेपाल की परियोजनाओं के लिए भारत देगा बड़ी मदद (अमर उजाला, 04.02.2020)
- रेगिस्तान में मिला 4800 खरब लीटर का जल भंडार (राष्ट्रीय सहारा, 08.02.2020)
- वर्ष 2024 तक पूरा करेंगे जल जीवन मिशन (राष्ट्रीय सहारा, 09.02.2020)
- गंगा सफाई में मदद करेगा सॉफ्टवेयर, आम लोगों को भी मिलेगी नदी के प्रदूषण की लाइव जानकारी (दैनिक भास्कर, 16.02.2020)
- राजस्थान : बेहतर जल प्रबंधन — प्लानिंग के लिए जल संसाधन विभाग को सीबीआईपी अवार्ड — 2020 से सम्मानित किया (पंजाब केसरी, 20.02.2020)
- जोजरी समेत देश की 8 छोटी नदियां होंगी पुनर्जीवित (राजस्थान पत्रिका, 22.02.2020)
- गंगा की अविरलता के लिए इंडोरामा ग्रुप से करार (राजस्थान पत्रिका, 25.02.2020)
- देश के सूखे—बाढ़ की समस्या को खत्म कर सकता है 'बुलढ़ाणा पैटर्न' (दैनिक जागरण, 28.02.2020)
- भूजल बढ़ाओ अभियान लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज (हिन्दुस्तान, 28.02.2020)

राज्यों से समाचार

पंजाब सरकार ने पंजाब जल संसाधन और विकास प्राधिकरण के गठन का मार्ग प्रशस्त करते हुए पंजाब जल संसाधन (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2020 पर एक अधिसूचना जारी की है.

इस प्राधिकरण को जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के अतिरिक्त पेयजल, घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों को निर्दिष्ट किए जाने वाले प्रशुल्क आदेश को जारी करने का अधिकार होगा.

सीबीआईपी पुरस्कार

डीएंडआर विंग, के.ज.आ. को सीबीआईपी पुरस्कार

डीआरआईपी हेतु सीपीएमयू, के.ज.आ. को सीबीआईपी पुरस्कार

केंद्रीय जल आयोग के डीएंडआर विंग को डिजाइन चुनौतियों से निपटने में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी) का पुरस्कार मिला.

उपरोक्त के अलावा, सेंट्रल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, के.ज.आ. को डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट (डीआरआईपी) के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए सीबीआईपी अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ. इन पुरस्कारों को दिनांक 19.02.2020 को नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री रतन लाल कटारिया, केंद्रीय राज्य मंत्री, जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिया गया.

डीएंडआर विंग, के.ज.आ. को सीबीआईपी पुरस्कार

सीपीएमयू, के.ज.आ. को सीबीआईपी पुरस्कार

इतिहास- राष्ट्रीय जल अकादमी

राष्ट्रीय जल अकादमी (जिसे पूर्व में सेंट्रल ट्रेनिंग यूनिट के रूप में जाना जाता था) की स्थापना केंद्रीय जल आयोग में वर्ष 1988 में की गई थी, जो जल संसाधन विकास और प्रबंधन में शामिल विभिन्न केंद्रीय / राज्य संगठनों के सेवारत अभियंताओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है.

सीटीयू में केवल एक / दो कार्यक्रमों से शुरुवात करके, एनडब्ल्यूए अब, जल क्षेत्र से संबंधित व्यापक विस्तार वाले विषयों के लगभग 35 कार्यक्रम चला रहा है और सालाना 10000 से अधिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है. एनडब्ल्यूए ने अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम मार्च 2012 से आयोजित करना शुरू किया. विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए, एनडब्लूए के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण, डीएल कोर्स की होस्टिंग के लिए मूडल प्लेटफ़ॉर्म, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के नामांकनों के आवेदनों के लिए आग्रह एवं अंतिम रूप देने, कामेट के साथ सहयोग आदि माध्यम से एनडबल्यूए को सहयोग दिया. अब तक, एनडब्लूए ने ऐसे बारह पाठ्यक्रम संचालित किए हैं.

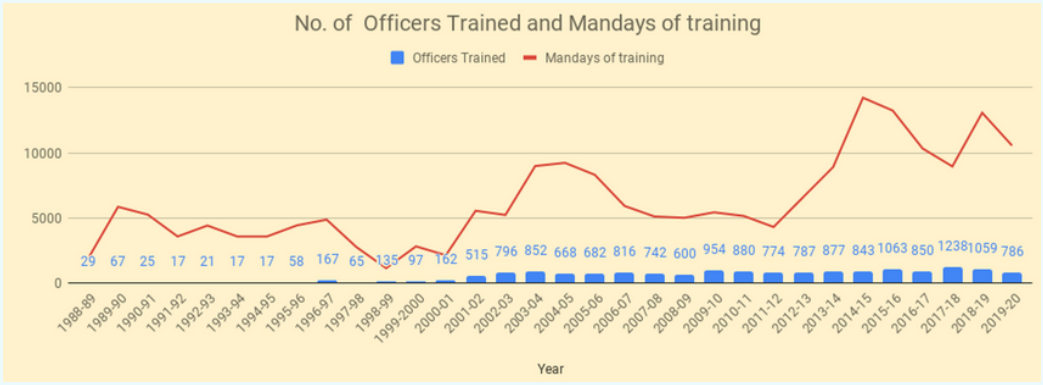

सीटीयू की पुरानी फोटो

केन्द्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का
एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक - मंडल

- श्री अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता (मा.स.प्र.)-मुख्य संपादक
- श्री अमरेंद्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता (ईएमओ)-सदस्य
- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (पीएमओ)-सदस्य
- श्री एच.एस. सेंगर , निदेशक (नदी प्रबंध समन्वय)-सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक (तकनीकी समन्वय)- सदस्य
- श्री प्रवीण कुमार, निदेशक (डब्ल्यूएसई)-सदस्य
- श्री पदमा दोर्जे ज्ञाम्बा, निदेशक (डबल्यूपीएंडपी समन्वय) -सदस्य
- श्री चैतन्य के, उप निदेशक (आईएसएम-2)-सदस्य
- श्री आर के शर्मा, उप निदेशक (डीएंडआर समन्वय)-सदस्य
- श्री शिव सुंदर सिंह, उप निदेशक (डब्ल्यूएसई)-सदस्य सचिव

अनुवाद : श्री शशि कान्त तिवारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (डब्ल्यूएसई), के.ज.आ., नई दिल्ली

अभिकल्प एवं प्रकाशन
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066
ई मेल: media-cwc@gov.in